RAJYA SABHA

Wedneday, the 18th August, 2004/27 Sravana, 1926 (Saka)

The House met at Eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

*321. श्री पी० के० माहेश्वरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में वर्ष 1992 से चलाये जा रहे केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम को, केवल पूर्ण सफाई अभियान कार्यक्रम के लिए स्वीकृत जिले में ही चलाने के निर्देशों के कारण, बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त कार्यक्रम में राज्य के 30 जिलों को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु परियोजनाएं भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकृति न प्रदान करने के क्या कारण हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) संपूर्ण स्वच्छता अभियान नामक मांग-जनित घटक शुरू करके केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में आबंटन आधारित घटक को धीरे-धीरे कम किया गया और 1.4.2002 से पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब सिर्फ संपूर्ण स्वच्छता अभियान ही कार्यान्वयन के अधीन है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। परियोजनाओं के अंतिम समूह को जुलाई, 2003 में स्वीकृत किया गया।

Central Rural Sanitation Programme

†*321. SHRI P. K. MAHESHWARI: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Rural Sanitation Programme being run in Madhya Pradesh since 1992 has been discontinued due to instructions of running this programme only in the districts approved for total sanitation campaign programme;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Government of Madhya Pradesh has sent projects for approval to Central Government for 30 districts of the State for inclusion in the said programme; and

(d) if so, the reasons for not according the approval and by when Central Government are likely to accord sanction for the same?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) Central Rural Sanitation Programme (CRSP) was restructured by Government of India in 1999 by introducing a demand driven component, namely the Total Sanitation Campaign (TSC). In the restructured CRSP, the allocation based component was gradually reduced and completely phased out with effect from 1.4.2002, and only the Total Sanitation Campaign (TSC) is under implementation now.

(c) and (d) TSC projects in all the districts of Madhya Pradesh have been sanctioned by Government of India. The last batch of projects was sanctioned in July, 2003.

श्री विक्रम वर्मा: सभापति महोदय, एथेंस ओलम्पिक में हमारे एक खिलाड़ी ने पदक जीता है.... ।

श्री सभापति: वह आ रहा है। आप तसल्ली रखिये।

श्री पी॰ के॰ माहेश्वरी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इस योजना के तहत कितनी राशि मध्य प्रदेश को दी गई है?

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में कुल योजना 422 करोड़ रुपये की स्वीकृत है, जिसमें अभी तक 89.7 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार की ओर से दिये गये हैं। राज्य सरकार को उसमें 15.19 करोड़ रुपये और लाभार्थियों से 6.07 करोड़ रुपये खर्च करने हैं।

श्री पी॰ के॰ माहेश्वरी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो योजना है, यह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये है और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 10 परसेंट से अधिक है, तो क्या मंत्री महोदय इसके लिए दी जाने वाली धनराशि में कुछ और वृद्धि करने की मंशा रखे हैं?

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, इस सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को तीन तरह से कराया जाता है। एक, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सबसिडी दी जाती है और तब इंडिविजयुअल बेनीफिशियरीज का शौचालय बनाया जाता है। दूसरे, सामूहिक शौचालय बनाने का भी प्रबंध है, जिसमें लाभार्थी को भी कुछ अंशदान देना पड़ता है। तीसरे, तमाम विद्यालयों में भी शौचालय बनाने का प्रबंध किया गया है। इसको तीन तरह से किया गया है। माननीय सदस्य की रुचि ग्रामीण स्वच्छता अभियान के बारे में है। इसलिए उसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है जिससे स्वच्छता अभियान सफल हो सके। उसमें ऐसा प्रबंध किया जाता है जिससे देश के एक भी आदमी को बाहर शौचालय के लिए न जाना पड़े और उनके लिए शौचालयों का प्रबंध कर दिया जाये।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: माननीय सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को सबसिडी दी जाती है। नम्बर दो, विद्यालयों को शौचालय बनाने के लिए भी धनराशि दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को अभी तक कितनी सबसिडी दी गई है? मेरा दूसरा सवाल है, कितने विद्यालयों को शौचालय बनाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, यह प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है। माननीय सदस्य का राज्यवार सवाल है या पूरे देश के लिए है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: आप मध्य प्रदेश के बारे में ही बता दीजिए।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: मध्य प्रदेश में जो इनडिविजुअल बेनीफिशरीज़ के लिए योजना है, वह 33 लाख 11 हजार 313 परिवारों के लिए योजना है कि इतने परिवारों के लिए इनडिविजुअल शौचालय बनवाए जाएं जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर का अलग है और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अलग है। फिर स्कूलों के टॉयलेट्स हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: वह अलग कितना है? सभापति महोदय, मैंने पूछा है कि कितना है लेकिन मंत्री महोदय नम्बर नहीं बता रहे हैं। मैंने नम्बर पूछा है। ...(व्यवधान)...मैंने दो बातें पूछी हैं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: ...(व्यवधान)...महोदय, टोटल प्रोजेक्ट आउटले 422 करोड़ 54 लाख रुपए है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: यह तो पूरा आपने ...(व्यवधान)...

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: जिसमें हम लोगों को केन्द्र सरकार से 79 करोड़ देना है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा। मैंने हिन्दी में बहुत सीधा सा सवाल पूछा है।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: हिन्दी में ही उत्तर दे रहा हूं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: वह आप बता नहीं रहे हैं। आप घुमा रहे हैं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछ लीजिए न।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: मैं फिर से पूछता हूं।

श्री बलबीर के॰ पुंज: महोदय, मंत्री महोदय अभी भी पूछ रहे हैं कि प्रश्न क्या है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: मैं फिर से पूछ रहा हूं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को सब्सिडी देने की बात आपने स्वच्छता अभियान में कही है। मध्य प्रदेश में कितने परिवारों को सब्सिडी दी गयी है और कितने विद्यालयों के लिए शौचालय बनाने के लिए आपने कितनी राशि मध्य प्रदेश में आबंटित की है? इन दो बातों का जवाब मुझे साफ-साफ चाहिए।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: मध्य प्रदेश का तो महोदय, पहले ही बता दिया।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: नहीं बताया है।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: 79.72 करोड़ रुपये दे दिए गये हैं, यहां से।...(व्यवधान).... वह तो पहले ही प्रश्न में है।....(व्यवधान)..... कुल 272 करोड़ की परियोजना है जिसमें से 79 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने रिलीज़ कर दिये हैं।

श्री सभापति: एक और इन्हें बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में शौचालय कितने बनाए हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: विद्यालयों के शौचालय ...(व्यवधान)...

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मध्य प्रदेश में अभी तक इनडिविजुअल बेनीफिशरीज़ के लिए ...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के॰ पुंज: महोदय, मंत्री जी तैयार होकर नहीं होते हैं। आप इन्हें निर्देशित कीजिए कि तैयार होकर आएं।

श्री सभापति: वे तैयार होकर आए हैं।

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: 1 लाख 20 हजार 951 इनडिविजुअल बेनीफिशरीज़ के लिए, 51 हजार 511 गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए और 1 लाख 72 हजार 462 गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बनाए गए हैं। स्कूलों के लिए 9 हजार 114 और सभी मिलाकर 12 लाख 9 हजार 51 बनाए गए हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। ....(व्यवधान)...

डॉ॰ (श्रीमती) नजमा ए॰ हेपतुल्ला: चेयरमैन साहब, मैं उस सवाल को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लड़कियों के जो स्कूल हैं, वहां शौचालय न होने की वजह से लड़कियां कितनी ड्रॉपआउट होती हैं और उड़ीसा में जिस स्कीम के तहत महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए, उससे ड्रॉपआउट का रेट कम हो गया। क्या सरकार के सामने कोई ऐसी स्कीम है, खास तौर से लड़कियों के लिए पूरे देश में शौचालय बनाने की?

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सरकार की योजना है कि देश के तमाम विद्यालयों में, आठ लाख प्राइमरी विद्यालय हैं और उसके बाद मिडल स्कूल तथा हाई स्कूल, सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पानी और पाखाना का इंतजाम कर दिया जाए। खास तौर से लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, हर स्कूल में यह प्रबंध है। टोटल सेनीटेशन कैम्पेन, जो सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता अभियान है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पानी और पाखाना का इंतजाम कर दिया जाए।

श्री सभापति: श्री तारिक अनवर ....(व्यवधान)....

श्रीमती सविता शारदा: यह गलत है। अभी तक नहीं हुआ है।....(व्यवधान)....

श्री बलबीर के पुंज: सभी स्कूलों में कर दिया गया है, ऐसा कहा गया है। ....(व्यवधान)...

श्रीमती सविता शारदा: कहीं पर भी नहीं है। किसी ग्रामीण ....(व्यवधान)....

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, यह गलतबयानी हो रही है। अभी कोलकाता कारपोरेशन की रिपोर्ट आई है। कोलकाता कारपोरेशन के बारे में बंगाल विधान सभा में उनके ऐजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 245 गवर्नमेंट ओन्ड स्कूलों में से सिर्फ 125 स्कूलों में ही संडास की व्यवस्था की जा सकी है, दूसरों में नही की जा सकी है। आप कह रहे है कि पूरे देश में कर दिया है लेकिन मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूं। ....(व्यवधान).....आप कहिए कि प्रावधान किया है।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने कहां कहा है कि सभी विद्यालयों में प्रबंध कर दिया गया है? ...(व्यवधान)... हमने यह कहा है कि टोटल सैनिटेशन कैम्पेन में सभी विद्यालयों में पानी और पाखाने का प्रबंध करने के लिए योजना बना दी गई है। उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 3744 करोड़ रुपए का उसमें प्रोजेक्ट बनाया गया है और महोदय, यह टोटल सैनिटेशन कैम्पेन 398 जिलों में था, जिसको बढ़ाकर नए 142 जिलों में और किया गया है और देश भर के करीब 66 जिलों में टोटल सैनिटेशन कैम्पेन के तहत सभी के लिए प्रबंध किया जा रहा है और मै समझता हूं कि सन् 2005 तक सभी विद्यालयों में पानी-पाखाने का इंतजाम कर दिया जाएगा।

Expenditure incurred on the Security of VIP's

*322. SHRI TARIQ ANWAR. Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Government are considering to reduce the security provided to the hundreds of VIPs,

(b) if so, the details thereof,

(c) the total number of VIPs who have been provided with the security; and

(d) the total expenditure incurred on the security of VIPs annually?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SRIPRAKASH JAISWAL). (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, यह सही है कि आज हमारे देश में आतंकवाद और उग्रवाद एक जटिल समस्या है और उसको ध्यान में रखकर अगर सुरक्षा प्रदान की जाती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु आज हमारे देश में जो सरकारी सुरक्षा दी जा रही है और ली